To supplement Government efforts in regard to poverty alleviation, the Private Sector is being encouraged to take up training programmes. Private ITI's contribute substantially towards skill upgradation through their development progrrammes and by providing necessary training infrastructure support for Training of Rural Youth for Self-employment (TRYSEM).

In addition, there is a National fund for Rural Development established in February, 1984 which attracts donations for rural development projects with tax concessions. It has been included under the category of activities eligible for 100 per cent income tax exemption under Section 35 CCA & 80 GGA of the Income Tax Act, 1961 consequent on the Amendment of the Direct Tax law (Amendment) Act 1989.

पिछड़े जिलों की पहचान के लिए दिशा- निर्देश

3340. **श्री नागमणिः**
चौधरी हरमोहन सिंह यादवः

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार मंत्री ने देश में पिछड़े जिलों का पता लगाने के लिए कुछ नए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दिशा-निर्देशों की घोषणा कब तक कर दी जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) किसी क्षेत्र का नियोजन और विकास तथा इसके लिए निधियों का आबंटन, मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार का दायित्व है। केन्द्र सरकार ने स्वतः किसी पिछड़े की पहचान नहीं की है। तथापि, वित्त मंत्रालय ने वित्तीय आधार-संरचनात्मक और औद्योगिक पैरामीटर पर आधारित कर रियायत के लिए औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को निर्दिष्ट करने हेतु दिनांक 3 सितम्बर, 1997 को जारी की गई अधिसूचना का.आ. संख्याएं 635 (ई) और 636 (ई) के तहत मार्गदर्शी सिद्धांत अधिसूचित किए हैं।

राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए निधि आबंटन

3341. **श्री ओंकार सिंह लखावतः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी) हेतु 1996-97 और 1997-98 के वर्षो के लिए कोई धनराशि स्वीकृत की थी;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के लिए राजस्थान हातु 1996-97 और 1997-98 के वर्षों के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी तथा वास्तव में कितनी धनराशि प्रदान की गयी; और

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने नौवीं पंचवर्षिय योजना में इस कार्यक्रम के लिए 580 करोड़ रुपए की मांग की है; यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) राजस्थान को सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, वर्ष 1996-97 और 1997-98 के लिए स्वीकृत और मुहैया कराई गई राशि इन प्रकार हैः

(करोड़ रुपये)

वर्ष	राशि
1996	85.63
1997-98	85.63

(ग) जी, नहीं।

बेरोजगारों की संख्या

3342. **श्री ओंकार सिंह लखावतः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में इस समय बेरोजगार लोगों की संख्या कितनी है और इनमें कितने लोग ग्रामीण क्षेत्रों से संहंधित है;

(ख) कुल बेरोजगार लोगों में शिक्षित बेरोजगार लोगों की संख्या कितनी है; और